बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

○ वर्ष: 23 ○ अंक: 158 ○ नई दिल्ली ○ शनिवार 21 जून 2025 ○ प्रभात कालीन ○ मूल्य: 3 रूपया ○ पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

हरियाणा पुलिस का एएसआई थाने में ले रहा था रिश्वत, एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोचा घूसखोर

हिसार । हरियाणा के हिसार में घूसखोर पुलिस वाला पकड़ा गया है। सिविल लाइन थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक रामनिवास को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता (एसीबी) की टीम ने गिरफ्तार किया है। एएसआई रामनिवास ने केस खारिज करने के नाम पर 30 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने एएसआई को सिविल लाइन थाने में पहुंच कर 15 हजार रुपये थमाए तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र निवासी बलवान व देवेंद्र का हिसार में एक व्यक्ति के साथ करीब एक लाख 30 हजार रुपये का लेनदेन था। जिसमें हिसार निवासी व्यक्ति ने देवेंद्र पर वर्ष 2023 में सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया।

डीयू के एडमिशन फॉर्म पर बवाल, मातृभाषा के सेक्शन से उर्दू को हटाकर शामिल किया मुस्लिम और बिहारी

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर्म को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 'मातृभाषा' के विकल्प से 'उर्दू' को हटा दिया गया है और उसकी जगह 'मुस्लिम' को मातृभाषा के रूप में शामिल कर दिया गया है.

यह न केवल संविधान के आठवीं अनुसूची का उल्लंघन है, बल्कि कई शिक्षकों और छात्रों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है. दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन फॉर्म में जहां आमतौर पर छात्रों से उनकी मातृभाषा पूछी जाती है, वहां इस बार 'उर्दू' गायब है और उसकी जगह 'मुस्लिम' को एक भाषा के रूप में दिखाया गया है. शिक्षकों और विशेषज्ञों का आरोप है कि यह न केवल गलत है, बल्कि इससे एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है. इसी के साथ मातृभाषा के कॉलम में 'बिहारी', 'मजदूर', 'देहाती', 'मोची', 'कुर्मी' इत्यादि जातिसूचक शब्द भी लिखे हैं. किरोरीमल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर और DUTA के निर्वाचित सदस्य रुद्राशीष चक्रवर्ती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, अगर यह पागलपन है, तो इसमें एक सोची-समझी योजना है. यूनिवर्सिटी का यह कदम स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक है. उर्दू को हटाना सिर्फ एक भाषा को हटाना नहीं है, यह उस साझा संस्कृति और साहित्य को मिटाने की कोशिश है जिसे उर्दू ने बनाया है. उन्होंने यह भी कहा कि डीयू के अधिकारी शायद यह मानते हैं कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, इसलिए उन्होंने 'उर्दू' की जगह 'मुस्लिम' को भाषा के रूप में जोड़ दिया. यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी को 'दूसरा' या 'अलग' साबित करने की कोशिश है. डीयू की प्रोफेसर और शिक्षकों की नेता अभा देव हबीब ने कहा, इस फॉर्म को 3 लाख से ज्यादा छात्र भरने वाले हैं. डीयू का यह पतन योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है.यह संविधान के खिलाफ है. भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उर्दू को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया है. ऐसे में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा इसे मातृभाषा के रूप में हटाना संविधान के खिलाफ माना जा सकता है.

प्रोफेसर देव हबीब आगे कहती हैं कि यह न केवल संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषा उर्दू का अपमान है, बल्कि यह समुदाय विशेष के प्रति एक सांप्रदायिक मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय को यह समझ नहीं कि मुसलमान भी अपने क्षेत्र के अन्य लोगों की तरह ही भाषाएं बोलते हैं?

सवाल यह उठ रहा है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय इस प्रकार की गलती कैसे कर सकता है. इसे न केवल अज्ञानता माना जा रहा है, बल्कि जानबूझकर की गई सांप्रदायिक छेड़छाड़ के रूप में देखा जा रहा है. रुद्राशीष चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि ष्ठ प्रशासन को पहले अंग्रेज़ी की बेसिक जानकारी लेनी चाहिए. उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ी में 'मातृभाषा' के लिए सही शब्द 'native language' है, न कि 'mother tongue'. 'Mother tongue' एक आम बोलचाल का शब्द है, लेकिन इसे किसी आधिकारिक फॉर्म में लिखना गलत है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कदम ने न केवल शिक्षाविदों को नाराज़ किया है, बल्कि यह एक बड़ी बहस को जन्म दे चुका है क्या शिक्षा संस्थानों में भी अब भाषाओं और समुदायों के नाम पर भेदभाव होने लगा है? फ़िलहाल डीयू प्रशासन ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया है.

क्लास रूम घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ईसीबी के सामने हुए पेश, आतिशी बोलीं- झूठे मामलों की सीरीज़ में एक नया एपिसोड

नई दिल्ली।

दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया को क्लासरूम घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इसको लेकर एक बार फिर आप बीजेपी पर हमलावर है. दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है, फिर से आप नेता से एक फर्जी केस के नाम पर पूछताछ की जा रही है. यह झूठा आरोप बीजेपी के झूठे मामलों की सीरीज़ में एक नया एपिसोड है. 10 साल से बीजेपी की केंद्र सरकार ने और उनकी एजेंसियों ने सिर्फ आप नेताओं पर फर्जी केस लगाए हैं. आतिशी का दावा है कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 200 से फर्जी ज्यादा केस लगाए हैं. हालांकि, 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, आईटी टीम, एसीबी आदि की जांच, रेड और फाइलो में किसी भी आप नेता के पास से एक रुपये के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला है. आप नेता आतिशी ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं बचा है, जिसके घर पर ईडी-सीबीआई की रेड न हुई हो, उनके लॉकर या बैंक अकाउंट न खंगाल कर देखे गए हों. इसके बावजूद किसी के पास भी भ्रष्टाचार का एक रुपया नहीं मिला. न ही किसी फर्जी केस में चवन्नी भर का सबूत भी कोर्ट में पेश किया गया. पूर्व सीएम आतिशी ने यह भी दावा किया, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद

केजरीवाल को बेल देते समय केंद्र की एजेंसी को फटकारा था. कहा था कि यह पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से कहा था कि आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा. राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है. इसके बाद भी आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है. आतिशी ने सवाल किया कि क्लासरूम घोटाले की जांच का क्या कारण है? इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही देते हुए कहा कि कारण केवल एक है. दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार 100 दिन में फेल हुई है. बीजेपी से सरकार चल नहीं रही. बिजली-पानी, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती फीस, शहर में बढ़ता क्राइम या दिल्ली की बाढ़ हो, आप किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल नजर आएगी. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जबसे बीजेपी सरकार आई है, इतने पावरकट हो रहे हैं. दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा, जिसने पिछले तीन महीने में लंबे-लंबे पावर कट न झेले हों. चाहे छतरपुर हो, मालवीयनगर, गोविंदपुरी, उत्तम नगर, पश्चिम विहार हो बुराड़ी हो या कोई और... दिल्ली के हर हिस्से में लंबे समय तक बिजली जाती है. क्या हम 2025 में जी रहे हैं? जहां भारत की राजधानी में बरसात आने पर बिजली नहीं दी जा सकती?

आतिशी ने कहा, न सिर्फ पावर कट हो रहे हैं, बल्कि बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं. NDMC के इलाके में 50 फीसदी से ज्यादा PPAC चार्ज बढ़ाए गए हैं और बढ़े हुए बिल आने शुरू हो गए हैं.

पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है. एक तरफ बारिश में सड़कों पर पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नलों से पानी नहीं आ रहा. DJB के इंजीनियर ऑफिस पर ताला लगाकर बैठे हैं, क्योंकि उनके सामने महिलाएं आकर मटके फोड़ रही हैं.

दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में सांप नहीं दिखी ये चीज, सीट पर चढ़कर चीखने लगी महिलाएं

नई दिल्ली । दिल्ली मेट्रो में आए दिन डांस, लड़ाई और आपत्तिजनक वीडियो आपने खूब देखे होंगे। हाल ही में दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में सांप दिखा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। जिसके बाद अब डीएमआरसी की ओर से इस वीडियो की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है। जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो के महिला कोच में सांप घुसने से हलचल मच गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं ने सांप को देखने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि सांप के दिखते ही महिलाएं इधर-उधर भाग रही हैं। कोई सीट पर चढ़ गई तो किसी ने इमरजेंसी बटन दबाया। सांप को देखते ही महिलाएं चिखने भी लगीं। वीडियो की शिकायत मिलने के बाद डीएमआरसी की ओर से एक्स पर जानकारी साझा की गई। डीएमआरसी ने बताया कि महिला कोच में सांप दिखने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी मिलते ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तुरंत कार्रवाई की। आगे लिखा कि ट्रेन को अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर खाली कराया गया।ट्रेन को गहन निरीक्षण के लिए डिपो भेज दिया गया। संबंधित टीम डिपो में ट्रेन की फुटेज और कोच की गहन जांच के बावजूद कोई सांप नहीं मिला। हालांकि, निरीक्षण के दौरान एक शिशु छिपकली देखी। आगे जानकारी देते हुए कहा गया कि डीएमआरसी यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हम यात्रियों से सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की तत्काल जानकारी साझा करने का आग्रह किया है।

आप सरकार ने बिना अनुमोदन 12,748 कमरों तक बढ़ाई परियोजना, मजदूरों के नाम पर खोले गए थे खच्चर खाते

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली में 37 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इसमें सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार ने 2,405 कक्षाओं की प्रारंभिक आवश्यकता के बावजूद, परियोजना का दायरा मनमाने ढंग से 7,180 समकक्ष कक्षाओं तक बढ़ा दिया था। इतना ही नहीं, बाद में उसे उचित मंजूरी या अनुमोदन के बिना 12,748 कमरों तक बढ़ा दिया। इससे लागत में भारी वृद्धि हुई। मजदूरों के नाम पर खच्चर खाते खोले गए थे। ईडी ने ऐसे खातों से जुड़ी 322 बैंक पासबुक बरामद की हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया (तत्कालीन शिक्षा मंत्री), सत्येंद्र जैन (तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री) और अन्य के खिलाफ 50 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय हेराफेरी से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटीडी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से 2023 के बीच लगभग 12,748 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है। प्रारंभिक आवश्यकता 2,405 कक्षाओं की थी, लेकिन परियोजना का दायरा मनमाने ढंग से 7,180 समकक्ष कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया। बाद में उचित मंजूरी या अनुमोदन के बिना 12,748 कमरों तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तावित अधिक विस्तृत विनिर्देशों को अनुचित रूप से अपनाया गया। डुप्लिकेट कार्यों का निष्पादन किया गया। प्राथमिकता-I और प्राथमिकता-II चरणों में 49.03त्न तक की लागत वृद्धि देखी गई। तलाशी के दौरान, ईडी ने एक निजी ठेकेदार के परिसर से काफी आपत्तिजनक सबूत बरामद किए। जब्त की गई सामग्रियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की मूल विभागीय फाइलें, तथा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के नाम और पदनाम वाले रबर स्टैम्प शामिल थे। ईडी ने मजदूरों के नाम पर खोले गए खच्चर खातों से जुड़ी 322 बैंक पासबुक भी बरामद कीं, जिनका इस्तेमाल वैध लेनदेन की आड़ में सरकारी धन की हेराफेरी करने के लिए किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न निजी ठेकेदारों और फर्जी संस्थाओं के जाली लेटरहेड, जिनका इस्तेमाल फर्जी खरीद रिकॉर्ड और फर्जी खरीद बिल बनाने के लिए किया गया था, पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। जीएनसीटीडी विभागों को जमा किए गए फर्जी चालान से संबंधित सबूत, जो फुलाए हुए या पूरी तरह से फर्जी दावे दिखाते थे, पाए गए हैं। ईडी ने इन्हें जब्त कर लिया है। तलाशी के दौरान कई डमी फर्म पाई गईं, जिनके पास कोई वास्तविक बुनियादी ढांचा, दस्तावेज या परिचालन वैधता नहीं थी, लेकिन दिखाया गया कि उन्हें अतिरिक्त कक्षाओं से संबंधित निर्माण गतिविधियों के लिए पर्याप्त भुगतान प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान पर्याप्त मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी द्वारा आगे की जांच जारी है।

तेंदुए की मौजूदगी की आशंका ने बढ़ाई स्थानीय लोगों में दहशत, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास कैमरा ट्रैप में तेंदुआ देखे जाने की सूचना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है. बीते मंगलवार को वन विभाग की विशेष टीम ने तेंदुए की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन तेंदुए की कहीं भी मौजूदगी नहीं दिखी. यह अभियान जगतपुर गांव के वन क्षेत्र में चलाया गया, जिसमें वन विभाग की टीमों के अलावा स्थानीय प्रशासन भी शामिल रहा. स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह चेतावनी (जंगली जानवर) देते हुए बोर्ड लगा दिया गया है और लगातार टीम से सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा गया है.

तेंदुए की तलाश में ड्रोन की भी ली जा रही मदद

स्थानीय किसानों से इस क्षेत्र में, कैमरा ट्रैप में तेंदुए की मौजूदगी का पता चलने के बाद वन विभाग ने विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों, ड्रोन और अन्य उपकरणों की मदद से इलाके की तलाशी ली. हालांकि,

अभी तक तेंदुए का कुछ पता नहीं चल पाया है. वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि संभावित खतरे को देखते हुए आसपास के गांवों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. गांववासियों को खास तौर पर रात के समय अकेले न निकलने और बच्चों को निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए हैं.

साथ ही, वन विभाग की ओर से स्कूली बच्चों व ग्रामीणों को तेंदुए से बचाव के तरीके समझाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क की फेंसिंग को मजबूत करने की मांग की.

बीते साल तेंदुए के हमले के तीन मामले

गौरतलब है कि, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पूर्व में भी तेंदुए के देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार इस इलाके में तेंदुए का स्थायी निवास नहीं है, और संभवतः यह किसी दूसरे क्षेत्र से भटक कर आया हो सकता है. लेकिन बीते साल अप्रैल महीने में तेंदुए के हमले के तीन मामले सामने आए थे, जिसे देखते हुए वन विभाग और प्रशासन सतर्क बना हुआ है. वन विभाग का कहना है कि जब तक तेंदुए की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह स्पष्टता नहीं हो जाती है तब तक निगरानी और तलाशी अभियान जारी रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि, तेंदुए को पकड़ कर सुरक्षित जंगल मे छोड़ दिया जाएगा. स्थानीय लोगों से सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है.

स्थानीय किसानों की माने तो 3 जनवरी को यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के राहाइसी क्षेत्र से सटे इलाके में तेंदुए को देखा गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी वन विभाग को दी गयी थी. उसके बाद मौके पर अधिकारियों की आवाजाही हुई थी और जगह -जगह चेतावनी के पोस्टर लगा कर गये थे, पर उस समय भी तेंदुए को नही पकड़ पाए थे और अब फिर से तेंदुए को देखने के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं.

दिल्ली में पैसों के विवाद में दोस्त ने दोस्त को मारा चाकू, बाइक भी लूटी, 2 गिरफ्तार

नई दिल्ली ।

पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना इलाके में चाकू मारकर बाइक लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने 24 घंटो के अंदर ही खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है. आरोपियों की पहचान, चंदन पासवान (23) और गौरव शर्मा (21) के रूप में हुई है. ये दिल्ली के सेवा धाम रोड और प्रताप नगर इलाके के रहने वाले हैं. पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 15 जून की सुबह लगभग 5 बजे की है, जब 17 वर्षीय युवक पर दो बदमाशों ने पुराने पैसों के विवाद को लेकर हमला कर दिया और उसकी मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए. सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस टीम ने घायल युवक को पहले जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया और तफ्तीश शुरू की. घायल युवक ने पुलिस को बताया कि घटना प्रतापनगर इलाके में हुई, जहां उसके दोस्त प्रियांशु और आरोपी गौरव के बीच पैसों को लेकर चल रहे पुराने विवाद को लेकर रंजिश में गौरव और उसके साथी चंदन ने उस पर चाकू से हमला किया और उसकी बाइक लूट ली. पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. एसीपी जसोद सिंह मेहता की देखरेख और एसएचओ प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. जिन्होंने घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला और फिर मुखबिरों की मदद से दोनों को दबोच लिया. उनके कब्जे से लूटी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी गौरव शर्मा हाल ही में हत्या के एक मामले में डासना जेल से बेल पर छूटा है. यह मामला 2024 में थाना लोनी बॉर्डर, गाज़ियाबाद में दर्ज हुआ था. जबकि पीड़ित युवक भी बाल आपराधिक कानून के तहत आरोपी रह चुका है.

कोरोना : आज एक और मरीज की हुई मौत

नई दिल्ली ।

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोविड लोगों को डरा रहा है। हर दिन मरीजों की मौत से आंकड़ा बढ़ रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई। एक दिन पहले भी दो महिलाओं ने कोरोना की वजह से दमतोड़ दिया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना से दिल्ली में 75 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। फेफड़ों के कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। शुक्रवार तक कोरोना से अब तक 16 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि कोरोना के 630 सक्रिय मरीज हैं। बीते गुरुवार को राजधानी में कोरोना से दो बुजुर्ग महिलाओं ने दम तोड़ दिया था। दोनों पहले से दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थीं। इलाज के दौरान संक्रमण होने पर स्थिति गंभीर हो गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के अनुसार, 67 साल की महिला को पहले से उच्च रक्तचाप के अलावा किडनी, निमोनिया, सेप्सिस, रिफ्रैक्टरी सेप्टिक शॉक की बीमारियां थीं। वहीं, 74 साल की महिला को पहले से कोरोनरी धमनी, आर्थराइटिस, सांस की बीमारी, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्टिक शॉक की बीमारियां थीं। इधर, बीते दिन की रिपोर्ट के अनुसार, एक जनवरी से अभी तक 15 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया।

वहीं दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 632 हो गई है। बुधवार को कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए, जबकि 100 मरीज स्वस्थ हो गए। राजधानी में एक जनवरी से अब तक 2580 मरीज ठीक हो चुके हैं।

हाईकोर्ट का पति को भगोड़ा घोषित करने के आदेश पर रोक से इनकार, लंदन में पत्नी की मौत के बाद से है फरार

नई दिल्ली । हाईकोर्ट ने पत्नी की संदिग्ध मौत के आरोपी को भगोड़ा घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। युवक पर पूर्वी लंदन में नौ महीने पहले संदिग्ध अवस्था में मृत मिली 24 वर्षीय पत्नी की हत्या में शामिल होने का आरोप है। युवक अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। न्यायमूर्ति प्रथिबा एम. सिंह ने कहा कि महिला की यूके में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यदि याचिकाकर्ता (पति) को गिरफ्तार किया जाता है तो वह कानूनी उपायों का लाभ उठा सकता है। आरोपी पति की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस नहीं दिया गया। मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और मेरी संपत्तियां जब्त होने का खतरा है। हालांकि, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है?

बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा कर हमने सरकार को जज, जूरी और जल्लाद बनने से रोका : सीजेआई

नई दिल्ली । प्रधान न्यायाधीश ने बुलडोजर जस्टिस पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए बताया है कि किस तरह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय पर प्रतिबंध लगाया और कार्यपालिका को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बनने से रोका। हम आपको बता दें कि भारत के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने इटली के शीर्ष न्यायाधीशों की सभा को संबोधित करते हुए पिछले 75 वर्षों में गरीबों और हाशिये पर पड़े लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के योगदान को रेखांकित करते हुए यह बात कही।

सीजेआई गवई ने कहा कि अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को मनमाने तरीके से गिराना, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करना और नागरिकों के आवास के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करना, असंवैधानिक है। सीजेआई ने कहा, कार्यपालिका (सरकार) एक साथ न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था, घर का निर्माण सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का एक पहलू है। उन्होंने कहा, एक आम नागरिक के लिए, घर का निर्माण वर्षों की मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं की परिणति होता है। एक घर केवल संपत्ति नहीं होता, बल्कि यह एक परिवार या व्यक्ति की स्थिरता, सुरक्षा और भविष्य की सामूहिक आशाओं का प्रतीक होता है। सीजेआई गवई ने कहा, पिछले 75 वर्षों को देखते हुए यह निर्विवाद है कि भारतीय संविधान ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि, निदेशक सिद्धांतों के कई पहलुओं को मौलिक अधिकारों के रूप में पढ़कर या कानून बनाकर लागू किया गया है।÷ हम आपको बता दें कि सीजेआई बीआर गवई भारतीय संविधान के 75 वर्षों के सफर से संबंधित विषय पर इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां संसद ने विधायी और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पहल की, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा से लेकर आजीविका तक के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को लागू करने योग्य मौलिक अधिकारों में बदलने का कार्य लगातार किया, जिन्हें बाद में संसद द्वारा प्रभावी बनाया गया।÷ सीजेआई ने कहा कि, ÷संविधान की 75 वर्षों की यात्रा सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में महान महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी है। उन्होंने कहा कि संविधान को अपनाने के तुरंत बाद भारतीय संसद द्वारा की गई प्रारंभिक पहलों में भूमि और कृषि सुधार कानून तथा पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां शामिल थीं। उन्होंने कहा कि इन पहलों का प्रभाव आज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत की न्यायपालिका के प्रमुख बनने वाले दूसरे दलित सीजेआई गवई ने कहा, शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया, वे संविधान की वास्तविक समानता और सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता का ठोस प्रमाण हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय एक अमूर्त आदर्श नहीं है और इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों के वितरण और लोगों के रहने की स्थितियों में जड़ें जमानी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी भी देश के लिए, सामाजिक-आर्थिक न्याय राष्ट्रीय प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास समावेशी हो, अवसरों का समान वितरण हो और सभी व्यक्ति, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सकें।'' भाषण देने के लिए आमंत्रित करने पर चैंबर ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स को धन्यवाद देते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में पिछले 75 वर्षों में भारतीय संविधान की यात्रा महान महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण सफलताओं की कहानी है। उन्होंने कहा, ''भारत के प्रधान न्यायाधीश के रूप में, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता इसके प्रावधानों का मसौदा तैयार करते समय सामाजिक-आर्थिक न्याय की अनिवार्यता के प्रति गहनता से सचेत थे। इसका मसौदा औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद तैयार किया गया था।''

विश्व शरणार्थी दिवस - मान्यता के माध्यम से एकजुटता

वैश्विक स्तरपर हर वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है जिसकी प्रतिवर्ष एक थीम होती है,जो 20 जून 2025 की थीम मान्यता के माध्यम से एकजुटता है।असल में,दुनिया भर में एक बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं। इनके साथ आए दिन प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा जैसी कई चुनौतियों के कारण इनको अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। जिसके बाद इन सभी को कई देशों में पनाह मिल जाती है। वहीं, कई देशों से इनको निकाल भी दिया जाता है। बेशक इन्हें पनाह मिल जाए, लेकिन वो सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाते।शरणार्थी के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इसके साथ ही इस दिन को मनाये जाने का एक अन्य उद्देश्य शरणार्थियों की बुरी दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उनकी समस्याओं का हल करना है,संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन और इसके प्रोटोकाल 1967, हालांकि भारत अमेरिका ने इसपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं,परंतु इसके अनुसार शरणार्थी सम्मेलन और इसका 1967 प्रोटोकॉल अत्यंत महत्वपूर्ण है शरणार्थी दुनियाँ के सबसे कमजोर लोगों में से हैं। यह सम्मेलन और प्रोटोकॉल उनकी सुरक्षा में मदद करता है। वे एकमात्र वैश्विक कानूनी साधन हैं जो स्पष्ट रूप से एक शरणार्थी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं। उनके प्रावधानों के अनुसार, शरणार्थी, कम से कम, किसी दिए गए देश में अन्य विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार के समान मानकों के पात्र हैं और, कई मामलों में,नागरिकों के समान व्यवहार।1951 के कन्वेंशन में कई अधिकार शामिल हैं और यह अपने मेजबान देश के प्रति शरणार्थियों के दायित्वों पर भी प्रकाश डालता है। 1951 के कन्वेंशन की आधारशिला गैर-रिफाउलमेंट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक शरणार्थी को उस देश में नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। शरणार्थियों द्वारा इस सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है,जिन्हें देश की सुरक्षा के लिए उचित रूप से खतरा माना जाता है, या विशेष रूप से गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है,उन्हें समुदाय के लिए खतरा माना जाता है। परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भाववाणी गोंदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूं कि अभी 1951 सम्मेलन तथा 1967 के प्रोटोकॉल को संशोधन करने की जरूरत आन पड़ी है?क्योंकि वर्तमान समय में हम अमेरिका- भारत-पाकिस्तान सहित अनेकों देशों में हो रहे गंभीर दंगों व आवर्ज़न विवादों के कारण माहौल दंगों में बदलने की संभावना हो गई है?भारत का ऑपरेशन पुशबैक व अमेरिका का टारगेटञ्च3000 से दंगा भड़क उठा है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे वैश्विक परिपेक्ष में जबरन स्वार्थी पलायन शरणार्थी बनाम भय उत्पीड़न हिंसा व पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन शरणार्थी। साथियों बात अगर हम अमेरिका की करें तो,वहां भी घुसपैठ का हाल कमोबेश ऐसा ही है। यह जब एक बार घुसपैठिया अंदर आ जाता है तो उसको डिपोर्ट करना भी इसी तरह एक लंबा और विवादास्पद मामला बन जाता है। अमेरिका में लॉस एंजिल्स न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ ऐसे शहर हैं,जहाँ अधिकारियों को इन घुसपैठियों से पूछताछ करने या उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति नहीं है। ये शहर डिपोर्ट करने के आदेशों या पुलिस के साथ सहयोग करने से साफ इनकार करते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन के राजनीतिक हथियार के रूप में देखते हैं।जून 2025 की शुरुआत से लॉस एंजिल्स में इसी से जुड़ा एक नाटक चल रहा है। यहाँ घुसपैठियों पर जब एक्शन चालू हुआ तो इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियाँ चलाई। यहाँ इसके बाद यूनियन नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार ने इसके बाद टाइटल 10 कानून के तहत 4,000 नेशनल गार्ड सैनिकों और 700 मरीन को तैनात करके जवाब दिया। इसके बाद तो बवाल और बढ़ा।

कई कारों को जला दिया गया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया, कई पत्रकारों को घायल कर दिया गया। इस पूरे बवाल से ट्रंप सरकार की घुसपैठियों को लेकर नीति और किसी शहर को उनके लिए स्वर्ग बनाने की राजनीति माना जा सकता है। इन सब चक्करों में डिपोर्टेशन और भी कठिन हो जाता है। भले ही अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति सख्त सीमा प्रवर्तन और भूमि से अवैध अप्रवासियों को हटाने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रणाली और कुछ विशिष्ट शहर इससे कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों बात अगर हम भारत की करें तो यहाँ भी वर्तमान में ऑपरेशन पुशबैक चल रहा है। इसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का प्रयास हो रहा है। यह कार्रवाई अभी कुछ हजार लोगों तक ही सीमित है।भारतीय फैशन,असल में एक बार जब अवैध प्रवासी किसी देश में प्रवेश कर जाते हैं तो चाहे वह भारत हो, अमेरिका फिर या यूरोप के देश, तो उन्हें वापस भेजना कानूनी अड़चन, राजनीतिक विरोध और एक्टिविज्म का एक चक्रव्यूह बन जाता है। कायदा तो यह होना चाहिए कि किसी देश में अवैध रूप से रहने वालों को उठा कर सीधे वापस भेज दिया जाना चाहिए। हालाँकि, यह लंबी अदालती लड़ाइयों, एक्टिविज्म और कानूनी दाँवपेंच में बदल गया है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ भारत जैसे देशों में घुसपैठियों को बाहर निकालना मुश्किल का काम है, वहीं पाकिस्तान धड़ाधड़ अफगानिस्तान के लोगों को निर्वासित कर रहा है। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी 2025 तक, पाकिस्तान ने 8 लाख़ से ज़्यादा अफ़गानों को बिना किसी बवाल के डिपोर्ट कर दिया है। साथियों बात अगर हम भारत अमेरिका के 1951 के शरणार्थी सम्मेलन व1967 के प्रोटोकॉल में शामिल नहीं होने की करें तो, भारत शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि भारत कानूनी रूप से इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा बाध्य नहीं है, जो शरणार्थियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं और देशों को उन्हें वापस अपने देशों में भेजने से रोकते हैं। हालांकि, भारत ने हमेशा पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों को मानवीय आधार पर स्वीकार किया है और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है। भारत का मानना है कि शरणार्थी समस्या एक द्विपक्षीय मुद्दा है और स्थिति सामान्य होने पर शरणार्थियों को अपने देशों में वापस लौट जाना चाहिए। भारत में शरणार्थियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, सभी व्यक्तियों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे वे भारत के नागरिक हों या नहीं। इसका मतलब है कि शरणार्थियों को भी इस अधिकार से सुरक्षा मिलती है, और उन्हें मनमाने ढंग से वापस नहीं भेजा जा सकता है। भारत में शरणार्थी समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट शरणार्थी नीति की आवश्यकता है जो शरणार्थियों के प्रबंधन के लिएपारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था का निर्माण करे। अमेरिका 1951 के अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन में शामिल नहीं है, लेकिन उसने 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, 1967 का प्रोटोकॉल 1951 के सम्मेलन के दायरे को व्यापक बनाता है।

सम्पादकीय...

इजरायल-ईरान युद्ध में भारत...

रूस-यूक्रेन एवं इजरायल-हमास के बीच युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और तीसरे मोर्चे इजरायल-ईरान के बीच भी युद्ध प्रारम्भ हो गया है। हालांकि इस बीच भारत-पाकिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ गया था परंतु भारत की बड़े भाई की भूमिका के चलते इस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने में सफलता मिल गई थी। दो देशों के बीच युद्ध में किसी एक देश का फायदा नहीं होकर बल्कि दोनों ही देशों का नुकसान ही होता है। परंतु, आवेश में आकर कई बार दो बड़े देश भी आपस में टकरा जाते हैं एवं इन दोनों देशों के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ देश खड़े हो जाते हैं जिससे कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि विश्व युद्ध छिड़ जाते हैं। वर्ष 1914 से वर्ष 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध एवं वर्ष 1939 से वर्ष 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध इसके उदाहरण हैं। इजरायल-ईरान के बीच हाल ही में प्रारम्भ हुए युद्ध में अमेरिका भी कूदने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सम्भव है कि ईरान की सहायता के लिए रूस एवं चीन भी इस युद्ध में कूद पड़ें एवं यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का स्वरूप ले ले। ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायल एवं अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं ताकि ईरान में उनके हितों को साधने वाली सरकार स्थापित हो सके। वैश्विक स्तर पर आज परिस्थितियां बहुत सहज रूप से नहीं चल रही है। विभिन्न देशों के बीच विश्वास की कमी हो गई है जिसके चलते छोटे छोटे मुद्दों को तूल दी जाकर आपस में खटास पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ देश, दो देशों के बीच, इन मुद्दों को हवा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आतंकवाद के मुद्दे को ही लें, यदि ये देश आतंकवाद से स्वयं ग्रसित हैं तो इनके लिए आतंकवाद बुराई की जड़ है और यदि कोई अन्य देश आतंकवाद को लम्बे समय से झेल रहा है तो इन देशों के लिए आतंकवाद कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बल्कि, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को प्रोत्साहन दिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चौधरी बन रहे कुछ देश अपनी विस्तरवादी नीतियों के चलते कई देशों में अपने हित साधने वाली सरकारों की स्थापना करना चाह रहे हैं एवं इन देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि ये देश आपस में लड़ाई प्रारम्भ करें। रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध इसका जीता जागता उदाहरण है । साथ ही, कुछ देशों की कथनी और करनी में पाए जाने वाले फर्क के चलते भी वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। चौधरी बन रहे देशों को तो उदाहरण पेश करते हुए अपनी कथनी एवं करनी में फर्क को समाप्त करना ही होगा। अन्यथा, वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां भयावह स्तर तक पहुंच सकती हैं। चूंकि इजरायल भी आतंकवाद से पीड़ित देश है एवं इजरायल की सीमाएं चार मुस्लिम राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं; यथा, उत्तर में लेबनान, दक्षिण पश्चिम में ईजिप्ट (एवं गाजा), पूर्व में जॉर्डन (एवं वेस्ट बैंक) एवं उत्तर पूर्व में सीरिया। अतः इजरायल अत्यधिक आक्रात्मकता के साथ आतंकवादियों (हम्मास एवं हूती आदि संगठनों) से युद्ध करता रहता है। इस्लाम के अनुयायी यहूदियों के कट्टर दुश्मन हैं, इसके चलते भी इजरायल के नागरिकों को आतंकवाद को लम्बे समय से झेलना पड़ रहा है। ईरान के बारे में तो कहा जा रहा है कि ईरान स्थित लगभग 60 प्रतिशत मस्जिदों में इबादत के लिए कोई भी व्यक्ति पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि ईरान में एवं ईरान द्वारा पड़ोसी देशों में फैलाए गए आतंकवाद से ईरान के मूल नागरिक अत्यधिक परेशान हैं। महिलाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से स्थानीय नागरिक बहुत दुखी हैं। अतः अब वे अपने पुराने धर्म जोरोस्ट्रीयन को अपनाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं अथवा इस्लाम धर्म का परित्याग करना चाह रहे हैं। जोरोस्ट्रीयन, ईरान का मूल धर्म हैं एवं यह अब ईरान के कुछ (बहुत कम) क्षेत्रों में सिमट कर रह गया है। भारत में भी जोरोस्ट्रीयन धर्म को मानने वाले पारसी समुदाय के कुछ नागरिक शांतिपूर्वक रह रहे हैं एवं भारत के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर निर्मित हो रही उक्त वर्णित परिस्थितियों के बीच भारत की विशेष भूमिका रह सकती है क्योंकि भारत के इजरायल एवं ईरान दोनों ही देशों के साथ आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। भारत, ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है एवं भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारी आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। चाबहार बंदरगाह का संचालन भी ईरान की सरकार के साथ भारतीय इंजीनियरों द्वारा ही किया जा रहा है। भारत और ईरान के बीच प्रतिवर्ष 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का विदेशी व्यापार होता है। दूसरी ओर, इजरायल भारत का रणनीतिक साझीदार है। भारत इजरायल से भारी मात्रा में सुरक्षा उपकरण भी खरीदता है। भारत और इजरायल के बीच प्रतिवर्ष 650 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि का विदेशी व्यापार होता है, इसमें भारत द्वारा इजरायल से आयात किये जाने वाले सुरक्षा उपकरणों की राशि शामिल नहीं है। कुल मिलाकर, भारत के इजराईल एवं ईरान, दोनों देशों के साथ बहुत पुराने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक रिश्ते हैं। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम; सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एवं सर्वे भवंतु सुखिन की भावना पर विश्वास किया जाता है। अतः भारतीय नागरिक सामान्यतः शांत स्वभाव के होते है एवं पूरे विश्व में ही भ्रातत्व के भाव का संचार करते हैं। आज 4 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के नागरिक विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। इन देशों में होने वाले अपराधों में भारतीय मूल के नागरिकों की संलिप्तता लगभग नहीं के बराबर पाई गई है। इसी कारण के चलते आज वियतनाम, जापान, इजरायल, आस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर जैसे कई देश भारतीय मूल के नागरिकों को अपने देश में कार्य करने एवं बसाने में सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी के देश यथा ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात आदि में भी लाखों की संख्या में भारतीय मूल के नागरिक निवास कर रहे हैं एवं शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न देशों में निवासरत भारतीय मूल के नागरिकों का रिकार्ड बहुत ही संतोषजनक पाया जाता है, क्योंकि, भारतीयों की मूल प्रकृति ही सनातन हिंदू संस्कारों के अनुरूप पाई जाती है एवं वे किसी भी प्रकार के कर्म में धर्म को जोड़कर ही इसे सम्पन्न करने का प्रयास करते हैं।

मोदी की सफल विदेश यात्रा

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की कनाडा यात्रा की सफलता के कई आयाम हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों में पुनः मिठास का दौर शुरू होने की जहां संभावना बढ़ गई है वहीं विश्व के अन्य देशों को भी सीधा सन्देश गया है कि भारत ऐसा शान्ति प्रिय देश है जो वार्ताओं द्वारा ही हर समस्या का हल चाहता है। श्री मोदी कनाडा जी-7 देशों के निमन्त्रण पर गये थे जहां के कैलगरी शहर में यह सम्मेलन हुआ। मगर जी-7 देशों के सम्मेलन में श्री मोदी ने जो सन्देश दिया है वह पूरे विश्व के लिए वर्तमान समय की चुनौतियों से जूझने का है। भारत के प्रधानमन्त्री ने आतंकवाद की बढ़ती समस्या की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के प्रति हम दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। श्री मोदी ने यह चेतावनी भी दी कि जो देश आतंकवाद को पनपाते या प्रश्रय देते हैं उन्हें हम किसी भी सूरत में पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं। आतंकवाद का मुकबला करने के लिए दुनिया के सभी देशों को निजी स्वार्थों व लाभ से ऊपर उठना होगा और इस समस्या का मुकाबला करना होगा। इस सन्दर्भ में उन्होंने जो वक्तव्य दिया वह सभी देशों के लिए विचारणीय है। भारत के प्रधानमन्त्री ने कहा कि हम देख रहे हैं कि जो देश खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें कुछ दूसरे अपनी कृपा से नवाज रहे हैं और आतंकवाद से आंखें मूंद रहे हैं। ऐसा वे निजी हितों को साधने की वजह से कर रहे हैं। ऐसा करना पूरी मानवता के विरुद्ध है। आतंकवाद मानवता के प्रति ही बहुत बड़ा अपराध है। श्री मोदी ने कहा कि इस बारे में मेरे कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो इस सभा स्थल पर मौजूद सभी देशों के प्रतिनिधियों से हैं। क्या हम आतंकवाद के प्रति वास्तव में चिंतित हैं ? क्या हम आतंकवाद के प्रति तभी गंभीर होंगे जब यह हमारी खुद की चौखट पर दस्तक देगा? क्या उन देशों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो इससे पीड़ित होते हैं? क्या हम ऐसे देशों को एक ही तराजू पर रखकर तोल सकते हैं? ऐसी स्थिति से क्या हमारे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अपनी प्रासंगिकता खोते नहीं जा रहे हैं? एक तरफ तो हम अपने हितों और स्वार्थों को साधने के लिए दूसरे देशों पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगाने में देर नहीं करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे देशों को पुरस्कृत करते हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं। यह दोहरापन क्यों ? ऐसा श्री मोदी ने क्यों कहा यह समझने की सख्त जरूरत है। श्री मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिये ही अमेरिका के दोहरेपन का खुलासा कर दिया। हम जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के फौजी सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दोपहर के भोजन पर निमन्त्रित किया। ट्रम्प जिस तरह की टेढ़ी चालें चलते हैं उनसे पूरी दुनिया अब अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है। मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे फौजी जनरल हैं जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भोजन का न्यौता दिया गया। आसिफ मुनीर ने अपनी बयानबाजी से भारतीयों का ध्यान भी खींचा था क्योंकि वह वही भाषा बोलते हैं जो कभी पाकिस्तान बनवाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बोला करता था। फिर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज बाकायदा आतंकवादी संगठनों को अपनी जमीन पर पनपाती है और आतंकवादियों को फौजी प्रशिक्षण भी देती है। अतः श्री मोदी का जी-7 देशों से यह कहना कि यदि आज हमने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, साफ बताता है कि भारत आतंकवाद के प्रति क्यों चिन्तित है और पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ क्यों दिलाना चाहता है। श्री मोदी ने अपने भाषण में विगत 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का भी जिक्र किया और उन देशों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की जिन्होंने इस घटना की कड़ी निन्दा की थी और भारत के प्रति सद्भावना व्यक्त की थी। श्री मोदी ने पहलगाम की घटना को भारत और हर भारतीय की आत्मा पर चोट बताया। श्री मोदी ने यह वक्तव्य देकर पूरी दुनिया को साफ तौर पर चेताया कि वे आतंकवाद के उनकी चौखट पर पहुंचने का इतजार न करें और इस बारे में निर्णायक फैसले लें। श्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिये बगैर आतंकवाद पनपाने व फैलाने में उसकी भूमिका पर भी कटाक्ष किया और कहा कि हमारे ही पड़ोस के देश में आतंकवाद को जमकर पनपाया जा रहा है। यह धरती आतंकवादियों के लिए सैरगाह बनी हुई है। अतः वैश्विक शान्ति और विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी नीतियां और सोच इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हों। इसलिए जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करता है उसे जिम्मेदार ठहराया जाये और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़े। श्री मोदी के उक्त उद्गारों से स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। इस सन्दर्भ में पहलगाम घटना के बाद भारत ने घोषित कर दिया था कि अब आगे से हर आतंकवादी घटना को भारत पर हमला माना जायेगा। श्री मोदी कनाडा के साथ ही क्रोएशिया व साइप्रस भी गये और वहां भी उन्होंने आतंकवाद और विश्व शान्ति की बात की। क्रोएशिया के साथ भारत के सांस्कृतिक व आर्थिक सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो इसका असर पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों पर भी पड़ा था। 1991 में क्रोएशिया युगास्लाविया से अलग होकर नया देश बना था। युगोस्लाविया के साथ आजादी के बाद से ही भारत के बहुत मधुर सम्बन्ध रहे हैं। युगोस्लाविया के स्व. राष्ट्रपति मार्शल टीटो पं. नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता थे। 1991 के बाद भारत के किसी प्रधानमन्त्री की यह पहली क्रोएशिया यात्रा थी। इस यात्रा में श्री मोदी ने क्रोएशियावासियों की भारत के प्रति बहुत गर्मजोशी भी देखी। कुल मिलाकर मोदी की यह विदेश यात्रा बहुत सफल

भविष्य का हथियार 'पानी'

जब सैमुअल टेलर कोलरिज़ ने अपनी कविता 'द राइम ऑफ द एंशिएंट मॅरिनर' में लिखा था, 'पानी-पानी हर जगह', तब शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन यही शब्द भविष्यवाणी साबित होंगे और आने वाले समय में पानी देशों के बीच एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन आज की हकीकत यही है और हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इसका एक ताज़ा उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले नदियों के जल को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने जो शुरुआती कदम उठाए उनमें से एक था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि की समीक्षा। यह संधि दोनों देशों के बीच छह नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। तकनीकी पहलुओं को एक तरफ रखें तो इसका सीधा-सा अर्थ यह निकलता है- पाकिस्तान को जल आपूर्ति से वंचित करना। या कम से कम यही संदेश भारत सरकार ने अपने देशवासियों और सीमा पार लोगों को देने की कोशिश की है। यह कोई खोखली धमकी नहीं है। इस संधि को निलंबित करने के निर्णय ने पाकिस्तान को गंभीर नुक्सान पहुंचाया है और इसके तात्कालिक ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक परिणाम भी होंगे। हालांकि सच्चाई यह है कि ऐसा करना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। सवाल उठते हैं- क्या भारत वास्तव में पाकिस्तान को पानी देना बंद कर सकता है या यह महज़ एक बयानबाज़ी है? क्या कोई भी देश पानी को हथियार बना सकता है? यह जल युद्ध पाकिस्तान को कितनी गहराई तक प्रभावित करेगा? भारत की तात्कालिक रणनीति और दीर्घकालिक योजना क्या है? इन सभी पहलुओं पर दो विशेषज्ञ डॉ. उत्तम सिन्हा और प्रोफेसर अंजल प्रकाश ने अपनी राय रखी और इस 'जल युद्ध' को व्यापक संदर्भ में समझाया। डॉ. सिन्हा एक लेखक और ट्रांसबाउंडरी जल मुद्दों के विशेषज्ञ हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में इंडस बेसिनअनइन्तेरुप्तेद, इंडस वाटर ट्रीटी और ट्रायल बय वाटर इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशामिल हैं। प्रोफेसर अंजल प्रकाश का कार्य क्षेत्र जल और जलवायु परिवर्तन है। वे विभिन्न स्तरों पर सरकार के साथ जुड़कर काम कर चुके हैं और जल को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने के पक्षधर रहे हैं। हालांकि, 'जल को हथियार' बनाने के मुद्दे पर दोनों विशेषज्ञों के मत भिन्न थे। जहां डॉ. सिन्हा इस शब्दावली से असहज दिखे, वहीं प्रो. प्रकाश इसके समर्थन में नज़र आए। डॉ. सिन्हा का मानना है कि जल का पुनर्गठन संभव है। भारत ने संधि को रद्द नहीं किया है, केवल निलंबित किया है जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और विश्व को यह संकेत देना है कि भारत की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है। अतीत में भारत ने इस संधि का राजनीतिकरण नहीं किया लेकिन पहलगाम घटना के बाद संयम की कोई गुंजाइश नहीं थी। भारत ने जल आपूर्ति को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बल्कि संधि के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जैसे बांधों की फ्लशिंग या पाकिस्तान को सूचनाएँ न देना एक रणनीतिक दबाव बनाया है। इसके विपरीत, प्रोफेसर अंजल प्रकाश जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने की वकालत करते हैं विशेषकर उस परिप्रेक्ष्य में जब पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का हिस्सा बना चुका है।

डोनाल्ड ट्रम्प की दुनिया

लॉस एंजिल्स अमेरिका का न्यूयार्क के बाद दूसरा बड़ा शहर है। यहां अमेरिका के लाजवाब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प,उनकी अपनी भाषा में, युद्ध लड़ रहे हैं। दंगों और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उन्होंने सेना तक को झोंक दिया है। महानगर की एक तिहाई जनसंख्या का जन्म अमेरिका से बाहर हुआ है। अधिकतर ब्लैक हैं तथा मैक्सिको और लेतिन अमेरिका के देशों से हैं। बड़ी संख्या अवैध भी हैं। भारी प्रदर्शन ट्रम्प सरकार की आप्रवासन नीति और प्रवासी समुदायों पर सरकारी दमन के खिलाफ किए जा रहे हैं। जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं वह वहां प्रवासियों के खिलाफ हाथ धोकर पड़े हैं। हमारे भी कुछ लोग दो विमानों में हथकड़ियां लगाकर भेज दिए गए थे, पर हमारी सरकार ख़ामोश रही। लॉस एंजिल्स में स्थिति लगभग गृह युद्ध जैसी बन गई है, क्योंकि जो पकड़ा जा रहा है वह हिंसक विरोध कर रहा है। कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ट्रम्प के कदम का डट कर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के खिलाफ अधिकारों के दुरुपयोग का मामला अदालत में दर्ज करवाया है। ट्रम्प का उल्टा जवाब था कि वह 'न्याय को रोकने' के आरोप में गवर्नर की गिरफ्तारी का समर्थन करते हैं। प्रवासियों का क्या किया जाए, यह अमेरिका का बड़ा धर्म संकट है। यह देश प्रवासियों ने बनाया है। डोनाल्ड ट्रम्प खुद प्रवासियों की तीसरी पीढ़ी हैं, पर अब जो अंदर आ चुके हैं जिनमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, वह दूसरों के लिए दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं। हमारे जो लोग अवैध रह रहे हैं वह चुपचाप अपनी ज़िन्दगी व्यतीत करते हैं। कोशिश होती है कि कानून का उल्लंघन न हो, पर जो ब्लैक और दक्षिण अमेरिका के देशों से वहां घुस आए हैं। उनमें से बहुत अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। वह बेरोज़गार हैं, बेघर हैं, बहुत ड्रग्स पर होते हैं। ज़िन्दगी से उन्हें कोई आशा नहीं है इसलिए हर क़िस्म के अपराध में संलिप्त रहते हैं। अमेरिका के हर बड़े शहर में ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई शरीफ़ आदमी कदम नहीं रख सकता। लॉस एंजिल्स में ही नक़ाबपोशों ने दो दर्जन बड़े स्टोर लूट लिए जिनमें एप्पल का स्टोर भी शामिल है। अमे?रकी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो मौक़ा मिलने पर बेधड़क स्टोर लूट लेते हैं। कुछ वर्ष पहले न्यूयार्क में रात के समय बिजली जाने पर असंख्य स्टोर लूट लिए गए। भारत में ऐसा नहीं होता। छोटी-मोटी चोरियां होती रहती हैं, पर सामूहिक तौर पर स्टोर लूटे नहीं जाते, जबकि रात को बिजली जाना तो आम बात है। ट्रम्प उस कानून का सहारा ले रहे हैं जिसके अनुसार वह नेशनल गार्ड को किसी भी जगह तैनात कर सकते हैं ÷अगर देश पर हमला हो रहा हो÷ या देश में ÷विद्रोह हो या विद्रोह का ख़तरा हो÷। वैध या अवैध प्रवासियों से क़ानून के उल्लंघन का तो ख़तरा हो सकता है, पर इन निहत्थे गरीब लोगों से विद्रोह का तो कोई ख़तरा नहीं है। अधिकारियों को 3000 प्रवासियों की दैनिक गिरफ्तारी का कोटा दिया गया है जिससे देश में भारी तनाव फैला हुआ है। देश के 12 राज्यों के 25 शहरों में प्रदर्शन फैल चुके हैं। कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं जहां प्रदर्शन न हो रहे हों। प्रदर्शनकारियों का नारा है %नो किंग'। वह ट्रम्प की तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध कर रहें हैं। इन प्रवासियों के बिना अमेरिका का गुज़ारा नहीं। ट्रम्प ने खुद माना है कि प्रवासियों के बिना उनके फ़ार्म, होटल और रेस्टोरेंट नहीं चल सकते। पर इस समय तो अमेरिका के राष्ट्रपति दमन पर लगे हुए हैं। अपने ही लोगों पर सेना के इस्तेमाल से भी वह परहेज़ नहीं कर रहे। तानाशाही प्रवृत्ति है इसलिए पुतिन या शी जिनपिंग जैसे लोग पसंद हैं। यूरोप जो सदा अमेरिका का साथी रहा है, को वह पसंद नहीं करते क्योंकि वह अधिक लिबरल है, उदार हैं।

कैलिफ़ोर्निया में बहुत लोग बाहर से आए हैं इसलिए विभिन्नता को स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक तौर पर यह स्टेट सदैव ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी का विरोधी रहा है। इसीलिए ट्रम्प ने भी अपना अभियान यहां से ही शुरू किया है। इससे उनके संघीय ढांचे की चूलें हिलेंगी और समाज में और विभाजन पैदा होगा। जिस तरह वह और उनकी सरकार हार्वर्ड और कोलम्बिया जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हैं उससे पता चलता है कि ट्रम्प लिबरल राय से कितनी नफ़रत करते हैं। हार्वर्ड तो विशेष तौर पर अमेरिका का क्राउन ज्यूल है, मुकुट का हीरा है। अमेरिका को उस जगह जाना जाता है जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। अमेरिका के आठ राष्ट्रपति यहां से पढ़ कर निकले हैं। अप्रैल में ट्रम्प हार्वर्ड को रिसर्च के लिए मिल रहे 2.2 अरब डॉलर का अनुदान रोक चुके हैं। वह यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के हार्वर्ड प्रवेश पर रोक लगा दी है जिसे अदालत ने रोक दिया है। वह हर उस संस्था के विरोधी हैं जो स्वतन्त्र राजनीतिक सोच को प्रोत्साहित करती है, जो अब तक अमेरिका की ताक़त रही है। वह हार्वर्ड को लोकतंत्र के लिए ख़तरा कह चुके हैं। स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर सुमित गांगुली का मानना है कि ट्रम्प जिस तरह यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं उससे उच्च शिक्षा जो अमेरिका की बड़ी शक्ति है, कमजोर हो रही है। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री जोशका फ़िशर ने सवाल किया है कि ट्रम्प जो हरकतें कर रहे हैं उससे अमेरिका को क्या मिला है? वह इसका उत्तर देते हैं, ÷ट्रम्प की नीतियों से पता चलता है कि यह अमेरिका को कमजोर करेंगी और यह भी हो सकता है कि यह अमेरिका को आत्म विनाश की तरफ़ ले जाएं÷। उनकी आशंका कितनी सही है यह समय बताएगा, पर यह तो सही है कि उनकी नीतियों के कारण अमेरिका अलग- थलग पड़ गया है। न्यूयार्क टाइम्स ने भी लिखा है कि अमेरिका के प्रति अविश्वास के कारण मित्र देश नई साझेदारियां तलाश रहे हैं।

इस समय तो न देश के अंदर और न ही बाहर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास करने को तैयार होगा। विदेशी मामलों में भी उनकी धमकियों और डींग के बावजूद एक उपलब्धि नहीं है। कहा था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों में यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, पर न पुतिन और न ही जलेंस्की ही उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में पढ़ रहे चीनी छात्रों पर पाबंदी लगा दी थी और प्रवेश पर रोक लगी दी थी। चीन पर 245त्न तक टैरिफ़ लगा दिया, पर जब चीन नहीं झुका तो 'डील' कर ली और अब कहता है कि चीनी छात्र तो 'सदा ही मेरे मनपसंद रहे हैं% !

अमेरिका में उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर बहुत चिन्ता व्यक्त की जा रही है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत अधिकार है। अदालतों के सिवाय उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ट्रम्प ने कहा था कि 'मैं किसी भी समस्या का हल कर सकता हूं'। पर शोर-शराबे के अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सके।

नवीनतम झटका इज़राइल का ईरान पर हमला है। ट्रम्प ने कहा है कि इज़राइल ने उन्हें हमला करने से पहले पूछा तक नहीं। अमेरिका की और फ़ज़ीहत क्या हो सकती है कि इज़राइल ने ईरान के प्रतिनिधिमंडल के उन सदस्यों को मार दिया जो उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से बात कर रहे थे। नेतन्याहू अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। ट्रम्प इस युद्ध से बाहर रहना चाहते हैं, पर आशंका है कि इज़राइल अमेरिका को बीच में खींच लेगा। इज़राइल ने ईरान के जनरल और न्यूक्लियर वैज्ञानिक मार दिए हैं, पर अभी तक ईरान के न्यूक्लियर संयंत्र नष्ट नहीं कर सका। वह इतनी गहराई पर हैं कि केवल अमेरिका के पास उन्हें नष्ट करने के बम हैं। ट्रम्प की सनक का शिकार अमेरिका की भारत नीति भी हो गई है। अचानक परिवर्तन आया है। वह शायद ख़फ़ा है कि भारत उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम का श्रेय नहीं दे रहा। वह 12बार कह चुके हैं कि मैंने करवाया, मैंने करवाया। पर भारत नहीं मान रहा। वह यह 'उपलब्धि' दिखाना चाहते हैं, क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए है नहीं। भारत के साथ रिश्ते अनिश्चित बन रहे हैं जबकि पाकिस्तान की सेना के साथ रिश्ता फिर से मजबूत किया जा रहा है। आपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका का रवैया भारत के प्रति बदला हुआ है। हमारी बात को नज़रंदाज़ किया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमान के कमांडर जनरल माइकल करिल्ला ने पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 'अद्भुत साझेदार है'।

पाकिस्तान को यह सर्टिफ़िकेट पहलगाम में हुई आतंकी घटना के दो महीने के अंदर दिया गया है। पाकिस्तान वह देश है जिसकी एबटाबाद सैनिक छावनी में अमेरिका का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन कई वर्ष छिपा रहा। पाकिस्तान के कारण ही अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, पर अब फिर वहां पाकिस्तान प्रेम जाग रहा लगता है। भारत को अपनी विदेश नीति फिर से तय करनी पड़ेगी। हम कोई छोटा- मोटा देश नहीं है। बंगलादेश के युद्ध के समय तो इंदिरा गांधी निक्सन के आगे डट गईं थीं।

अब फिर अमेरिका के सामने डटने का समय है। भारत और अमेरिका की स्ट्रैटेजिक साझेदारी अब पतली हो रही है। विश्वास ख़त्म हो गया है, पर भारत एकमात्र नहीं है, दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास करता हो।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

सपाट शुरुआत के बाद बाजार ने लगाई लंबी छलांग; सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक उछला, निफ्टी में भी तेजी

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार की शुक्रवार को सपाट शुरुआत हुई। हालांकि, बाद में बाजार ने लंबी छलांग लगाई। 12 बजे के करीब सेंसेक्स 750 अंकों से ज्यादा की छलांग लोकर कारोबार कर रहा था। ऐसे ही निफ्टी 250 अंक उछलकर 25 हजार के पार पहुंच गया। इससे पहले बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 81,354.85 अंक पर खुला था। गिरावट के दौरान सेंसेक्स 81,323.20 अंकों तक पहुंचा था। बीते दिन यह 81,361.87 अंक पर बंद हुआ था। ऐसे ही निफ्टी भी गिरावट के साथ 24,787.65 अंक पर खुला था। गिरावट के दौरान यह 24,783.65 अंकों तक पहुंच गया था। बीते दिन निफ्टी 24,824.75 अंकों पर बंद हुआ था। इस बीच शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे बढ़कर 86.58 पर पहुंच गया था।

एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी फंड प्रवाह के चलते तीन दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। सपाट शुरुआत के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बाद में शुरुआती कारोबार में 289.43 अंक चढ़कर 81,651.30 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 88.25 अंक चढ़कर 24,881.50 पर पहुंच गया।

किसे फायदा-किसे नुकसान?

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटरनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और मारुति सबसे ज्यादा फायदे में रहीं। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 934.62 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 605.97 करोड़ रुपये के इक्विटी खरीदे।

एशियाई और अमेरिकी बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार बंद रहे। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.45 फीसदी गिरकर 76.92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

जानकार बताते हैं कि निफ्टी एक महीने से 24,500-25,000 की सीमा के भीतर कारोबार कर रहा है, आगे भविष्य में इसके इसी सीमा के भीतर रहने की संभावना है। सीमा का ऊपरी हिस्सा केवल इस्राइल-ईरान संघर्ष के कम होने या युद्ध के अचानक समाप्त होने की खबर पर ही उठापटक दिखेगी। सीमा का निचला हिस्सा इसके असर से दूर ही रहेगा। जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, %अगर युद्ध जारी रहता है और कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर से ऊपर जाती है तो सीमा का निचला बैंड टूट जाएगा।

बीते दिन का हाल

इससे पहले बीते दिन यानी गुरुवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 82.79 अंक या 0.10 फीसदी गिरकर 81,361.87 पर बंद हुआ था। ऐसे ही निफ्टी 18.80 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 24,793.25 पर बंद हुआ था।

एक नजर

करार : भारत में बनेंगे लीप इंजन के टर्बाइन फोर्ज्ड पार्ट्स; बंगलूरू में होगा निर्माण हैदराबाद में रखरखाव केंद्र

नई दिल्ली । हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लि. (एचएएल) ने फ्रांस की इंजन निर्माता सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एचएएल भारत में लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्शन (लीप) इंजन के लिए महत्वपूर्ण टर्बाइन फोर्ज्ड पार्ट्स का निर्माण करेगा और सफ्रान को सप्लाई करेगा। ये पार्ट्स, एयरबस ए-320 नियो और बोइंग-737 मैक्स जैसे विमानों में इस्तेमाल होने वाले इंजन के लिए होंगे। इस साझेदारी से भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति को बढ़ावा मिलेगा। एचएएल के बयान के अनुसार, इस समझौते को फ्रांस के ले-बॉरगेट में 55वें पेरिस एयर शो में अंतिम रूप दिया गया। समझौते पर एचएएल के एलसीए डिवीजन के महाप्रबंधक अब्दुल सलाम और सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन के उपाध्यक्ष (खरीद) डोमिनिक डुप्यू ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों कंपनियों के बीच अक्तूबर 2023 और फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का विस्तार है। एचएएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डीके सुनील ने कहा, यह दीर्घकालिक साझेदारी अब उन्नत चरण में पहुंच रही है। हमें लीप इंजन की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान देने पर गर्व है। वहीं, डोमिनिक डुप्यू ने कहा, एचएएल हमारी वैश्विक सोर्सिंग रणनीति में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। यह समझौता भारत में हमारी औद्योगिक उपस्थिति, तेजी से बढ़ते नागरिक उड्डयन बाजार के लिए लीप इंजनों के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। इस अनुबंध के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलूरू स्थित अपनी अत्याधुनिक रिंग रोलिंग सुविधा में लीप इंजन के लिए फोर्ज्ड पार्ट्स बनाएगा, जिससे वैश्विक एयरलाइंस की बढ़ती मांग पूरी की जाएगी। सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। कंपनी के देश में पहले से ही पांच उत्पादन केंद्र हैं और अब हैदराबाद में लीप इंजन के रखरखाव के लिए छठा केंद्र खोलने की योजना बना रही है।

खाद्य तेल की किल्लत का खतरा: कांडला बंदरगाह पर फंसे जहाज, बढ़ सकती हैं कीमतें

बिजनेस डेस्क । आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण कांडला पोर्ट पर जहाजों की भारी भीड़ और माल उतराई में हो रही देरी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई व्यापारिक संगठनों ने सरकार को चेताया है कि यदि पोर्ट की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो देशभर में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और तेल महंगा हो सकता है। SEA के अनुसार, नवंबर 2024 से मई 2025 के बीच भारत का खाद्य तेल आयात 9फीसदी गिरकर 78.8 लाख टन रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 86.7 लाख टन था। भारत हर महीने लगभग 7.5 लाख टन पाम ऑयल आयात करता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। कांडला पोर्ट पर फिलहाल 157,000 टन तेल लादे 8 जहाज बर्थिंग का इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 2 जहाजों से 45,000 टन तेल की अनलोडिंग हो रही है अगले कुछ दिनों में 159,000 टन तेल के साथ 5 और जहाज पहुंचने वाले हैं पोर्ट अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल 6 खाद्य तेल और 6 रसायन वाले जहाज एंकर पर हैं कांडला पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह के अनुसार, मई में आयात शुल्क में कटौती के बाद खाद्य तेल की आवक में अचानक तेज़ी आई है। उन्होंने कहा कि औसतन 8-10 दिन की प्रतीक्षा हो रही है लेकिन संचालन प्रक्रियाओं को सख्त किया गया है और समाधान की कोशिशें जारी हैं। SEA ने आरोप लगाया है कि कई जहाजों को पूरा माल खाली करने से पहले ही बर्थ से हटा दिया गया, जिससे आयातकों को डिमरेज शुल्क जैसे भारी नुकसान उठाने पड़ रहे हैं।

इजरायल की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का वार, खर्च बेकाबू, सरकारी खजाना खाली होने की कगार पर

बिजनेस डेस्क । मिडिल ईस्ट में जारी ईरान-इजरायल संघर्ष अब महज सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर आर्थिक जंग में तब्दील हो चुका है। इजरायल हर दिन करीब 63 अरब रुपए (725 मिलियन डॉलर) खर्च कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बन गया है और सरकारी खजाना तेजी से खाली होता जा रहा है। यह खुलासा इजरायली सेना के पूर्व वित्तीय सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (रिजर्व) रीम अमीनाच ने किया है। उनके अनुसार, युद्ध शुरू होने के सिर्फ पहले दो दिन में ही इजरायल ने 1.45 अरब डॉलर (लगभग 12,000 करोड़) खर्च कर दिए जिसमें हमला और रक्षा दोनों खर्च शामिल हैं। इजरायल ने ईरान पर जो पहला हमला किया, उसमें विमानों के उड़ने और हथियारों के इस्तेमाल का खर्च 593 मिलियन डॉलर था। बाकी पैसा मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम और रिजर्व सैनिकों को बुलाने में खर्च हुआ। अमीनाच ने यह भी कहा कि यह सिर्फ सीधा खर्च है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे जीडीपी पर असर अभी नहीं मापा जा सकता। असली बिल तो तब पता चलेगा जब नागरिक संपत्ति को हुए नुकसान और काम में कमी जैसे खर्चों को जोड़ा जाएगा। युद्ध के चलते इजरायल की आर्थिक विकास की उम्मीदें कम हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने पहले ही इस साल के लिए GDP का 4.9 फीसदी घाटा तय किया था। यह लगभग 27.6 अरब डॉलर है। देश के बजट में इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा गया था लेकिन वह ज्यादातर गाजा युद्ध में ही खर्च हो गया। अब ईरान के साथ चल रहे युद्ध के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इस युद्ध के कारण मंत्रालय ने 2025 के लिए विकास दर का अनुमान 4.3फीसदी से घटाकर 3.6फीसदी कर दिया है। इसका मतलब है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पहले जितनी तेजी से बढ़ने की उम्मीद थी, अब उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इस युद्ध का असर सिर्फ इजरायल-ईरान तक सीमित नहीं। 13 जून के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 64-65 डॉलर से बढ़कर 74-75 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी हैं। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह बड़ा झटका है। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, अगर तेल कीमतें औसतन 10 डॉलर बढ़ती हैं, तो भारत को 13-14 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है। इससे चालू खाता घाटा भी 0.3 फीसदी तक बढ़ सकता है।

16 अरब लॉगइन हुए लीक, एपल, गूगल जैसी कंपनियों के ग्राहकों के लिए बढ़ा खतरा

वॉशिंगटन । साइबर सिक्योरिटी शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि 16 अरब लॉगइन क्रेडेंशियल चोरी हुए हैं, जिनमें पासवर्ड भी शामिल हैं। यह तकनीकी इतिहास के सबसे बड़े लीक में से एक बताया जा रहा है। इस डेटा लीक से एपल, गूगल, फेसबुक, गिटहब, टेलीग्राम आदि प्लेटफॉर्म्स की किसी भी ऑनलाइन सेवा में सेंधमारी हो सकती है। यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब कई रिपोर्ट में 18 करोड़ रिकॉर्ड वाले रहस्यमयी डेटाबेस की मौजूदगी का पता चला है, जो एक वेब सर्वर पर असुरक्षित रूप से मौजूद है। रिसर्च में पता चला है कि यह एक बहुत बड़े लीक का सिर्फ कुछ हिस्सा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शोधकर्ताओं ने 30 डेटासेट का पता लगाया है, जिसमें से प्रत्येक में 3.5 अरब रिकॉर्ड हैं। जिसमें सोशल मीडिया और वीपीएन लॉगइन के साथ ही कॉरपोरेट और डेवलेपर प्लेटफॉर्म आदि जानकारी है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लीक डेटा का इस्तेमाल धोखाधड़ी, अकाउंट टेकओवर करने और बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज के लिए हो सकता है। यह बड़े पैमाने पर शोषण करने का खाका है। डेटा उल्लंघन के कारण ही गूगल अपने यूजर्स को पासवर्ड और दो कारक प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा को अपग्रेड करने की सलाह दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे टूल का उपयोग करना अहम है, जो आपके खाते को स्वचालित रूप से सुरक्षित करते हैं और आपको धोखाधड़ी से बचाते हैं।

चीन पहुंचे कीवी पीएम लक्सन, शी जिनपिंग से की मुलाकात; व्यापारिक संबंधों पर दिया जोर

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। लक्सन ने इस बैठक में दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। यह बैठक शुक्रवार को हुई। क्रिस्टोफर लक्सन 2023 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली चीन यात्रा पर हैं। वे चीन के वाणिज्यिक केंद्र शंघाई में अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ दो दिनों की बैठकों के बाद बीजिंग के लिए रवाना हुए। लक्सन चीन के साथ स्वस्थ व्यापार संबंध बनना चाहते हैं। चीन न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। वे चीन के भू-राजनीतिक मतभेदों और अमेरिका के साथ चीन के टकराव को नजरअंदाज करके व्यापार वार्ता पर जोर दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के माल और सेवाओं के निर्यात में चीन का योगदान 20 प्रतिशत से अधिक है। न्यूजीलैंड ने इस सप्ताह चीनी पर्यटकों के लिए वीजा में सीमित ढील देने की घोषणा की, जो पर्यटन राजस्व का एक

प्रमुख स्रोत है।

बैठक में दूसरे मुद्दों को भी उठाया

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमारे व्यापारिक और आर्थिक संबंध एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों देशों की समृद्धि में योगदान करते हैं। लक्सन ने कहा इस बैठक में दूसरे मुद्दों को भी उठाया गया। इसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चल रहे तनाव को कम करने की जरूरत और युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने के लिए चीन की ओर से निभाई जा सकने वाली बड़ी भूमिका को बताया। लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैठक से संबंधित पोस्ट किया। इसमें कहा गया कि एक जटिल दुनिया में, खुला संवाद पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

शी ने मतभेदों को दूर करने पर दिया जोर

चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि शी ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को दूर रखते हुए साझा आधार पर सहमत होने की जरूरत है। उन्होंने व्यापार और निवेश सहयोग को गहरा करने और जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाशने का आह्वान किया।

चीन ने किए न्यूजीलैंड और कुक द्विप के संबंध खराब

यह वार्ता ऐसे समय में हुई है, जब चीन और कुक द्वीप समूह के बढ़ते संबंधों को लेकर न्यूजीलैंड ने चिंता जताई। एक दिन पहले न्यूजीलैंड ने बड़ा कदम उठाते हुए कुक द्विप को दी जाने वाली लाखों डॉलर की मदद को रोक दिया। दरअसल, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर के इस छोटे से द्विप का सबसे बड़ा वित्तपोषक है। हाल के वर्षों में चीन के साथ संबंधों को लेकर अन्य प्रशांत द्वीपों और उनके बड़े क्षेत्रीय समर्थकों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच संबंध खराब हुए हैं। इसके पीछे है चीन, जो प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। लक्सन के कार्यालय ने बताया कि वे अगले दौरे पर यूरोप जाएंगे, जहां उनकी ब्रुसेल्स और नीदरलैंड में बैठकें होंगी। वह यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ व्यापार, सुरक्षा और भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नीदरलैंड में, वह अगले सप्ताह हेग में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में आमंत्रित अतिथि हैं।

जीएसएमए की रिपोर्ट : मोबाइल उद्योग ने पांच साल में घटाया 8 फीसदी उत्सर्जन, नेट जीरो लक्ष्य अब भी दूर

नई दिल्ली।

मोबाइल उद्योग ने वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में अच्छा प्रयास किया है। उद्योग ने 2019 से 2023 के बीच अपने कार्बन उत्सर्जन में 8 फीसदी की कटौती की है। इस अवधि में मोबाइल कनेक्शन में 9 फीसदी और डाटा ट्रैफिक में चार गुना तक की वृद्धि हुई। हालांकि, नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्योग को मौजूदा रफ्तार से दोगुनी तेजी से यानी 2030 तक हर साल औसतन 7.5 फीसदी की दर से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी होगी।

ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन (जीएसएमए) की ताजा रिपोर्ट मोबाइल नेट जीरो-2024 के मुताबिक, डाटा और कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के बावजूद मोबाइल उद्योग के कार्बन उत्सर्जन में 4.5 फीसदी की अतिरिक्त कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह चार

फीसदी बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल बाजार चीन ने पहली बार 2024 में कार्बन उत्सर्जन चार फीसदी घटाया है, जबकि 2019 से 2023 के बीच इसमें 7 फीसदी की वृद्धि हुई थी। 5जी नेटवर्क वाले इस देश में अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल चार गुना बढ़ा है, जो उत्सर्जन में कमी का प्रमुख कारण है। अक्षय ऊर्जा के उपयोग से उत्सर्जन में आई 1.6 करोड़ टन की कमी 2023 में मोबाइल कंपनियों की ओर से इस्तेमाल कुल बिजली में सौर और पवन जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 37 फीसदी पहुंच गई, जबकि 2019 में यह सिर्फ 13 फीसदी थी। इस बदलाव से कार्बन उत्सर्जन में 1.6 करोड़ टन की कटौती करने में मदद मिली है। जीएसएमए की क्लाइमेट एक्शन टास्कफोर्स में अब 77 मोबाइल ऑपरेटर शामिल हैं, जिनकी वैश्विक मोबाइल कनेक्शनों में 80 फीसदी हिस्सेदारी है। क्षेत्रीय स्तर पर यूरोप ने उत्सर्जन में 56 फीसदी, उत्तर अमेरिका ने 44 फीसदी और दक्षिण अमेरिका ने 36 फीसदी तक गिरावट दर्ज की। एशिया और अफ्रीका में भी उत्सर्जन कम करने के प्रयास बढ़ रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन घटाने में तेजी के पीछे मुख्य वजह है...मोबाइल नेटवर्क का अधिक ऊर्जा-दक्ष बनना और डीजल जनरेटर की जगह स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल। कई देशों में सरकारी नीतियों और ऊर्जा बाजार में सुधार से यह संभव हो पाया है। जीएसएमए के सर्वे के मुताबिक, एक सकारात्मक प्रवृत्ति यह भी सामने आई है कि पुराने मोबाइल फोन के दोबारा इस्तेमाल की लोगों में रुचि बढ़ रही है। इसलिए, सेकंड हैंड मोबाइल फोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जबकि नए फोन की बिक्री धीमी हुई है। 2027 तक सेकंड हैंड मोबाइल फोन बाजार के 150 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

एचडीएफसी फाइनेंशियल का आईपीओ 25 जून को खुलेगा, मूल्य दायरा 700-740 रुपए प्रति शेयर

नई दिल्ली। एचडीएफसी बैंक की अनुषंगी इकाई एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने 12,500 करोड़ रुपए के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 700-740 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 25 जून को खुलेगा और 27 जून को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 24 जून को बोली लगा पाएंगे। यह कंपनी का पहला आईपीओ है। आईपीओ 2,500 करोड़ रुपए के नए शेयर और प्रवर्तक एचडीएफसी बैंक द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। एचडीएफसी बैंक की उसकी गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाई एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में वर्तमान में 94.36 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी के शेयर के दो जुलाई को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

औंधे मुंह गिरे सोने के भाव, इतना हुआ सस्ता 10g पीली धातु का रेट

बिजनेस डेस्क । सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आज लगातार तीसरा दिन है जब सोने की कीमतें टूटी हैं। हालही में सोने ने एक लाख के आंकड़े को पार किया था। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए सही समय साबित हो सकता है। शुक्रवार, 20 जून 2025 को सोने का भाव 0.47 फीसदी गिरकर 98,863 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 1.43 फीसदी लुढ़की है, ये 1,05,857 रुपए प्रति किग्रा पर है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 150 रुपए टूटकर 1,00,560 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,00,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बृहस्पतिवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 150 रुपए की गिरावट के साथ 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक जिंस और मुद्रा जतिन त्रिवेदी के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत रुख पर बाजार की प्रतिक्रिया के कारण सोने में उतार-चढ़ाव रहा, जिसने तत्काल ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का संकेत दिया। त्रिवेदी ने कहा कि फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के बावजूद, ईरान और इजरायल के बीच चल रहा भू-राजनीतिक तनाव सोने को सुरक्षा प्रदान करता है। हाजिर चांदी एक प्रतिशत गिरकर 36.37 डॉलर प्रति औंस रह गई।

पावरफुल इंडिया : चीन-यूएस के बाद बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत, स्वच्छ ऊर्जा बनी बड़ी ताकत

नई दिल्ली। भारत पिछले पांच वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बिजली उत्पादन वृद्धि में अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही भारत से आगे हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कई कारणों से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें वाणिज्यिक एवं आवासीय स्थानों का विस्तार, एयर कंडीशनर (एसी) व अन्य घरेलू उपकरणों के इस्तेमाल में वृद्धि और उद्योगों की बढ़ती मांग शामिल है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत में सभी ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली उत्पादन के इस विस्तार का प्रमुख चालक अक्षय ऊर्जा की ओर मजबूत झुकाव है, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा और विशेष रूप से सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) परियोजनाओं में बड़े स्तर पर निवेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में भारत में गैर-जीवाश्म ऊर्जा परियोजनाओं में किए गए कुल निवेश में सौर पीवी की आधे से अधिक हिस्सेदारी रही। 2024 में भारत के बिजली क्षेत्र में किए गए कुल निवेश का 83 फीसदी हिस्सा

स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर खर्च किया गया। भारत के बिजली क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने में सरकारी नीतियों का अहम योगदान है, जो बिजली उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर) और ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी क्षेत्रों में 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में पिछले दो वर्षों में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट का कारण व्यापक आर्थिक और क्षेत्र आधारित चुनौतियों का मिश्रण है। हालांकि, भारत के बिजली क्षेत्र में दीर्घकालिक रुझान सकारात्मक बना हुआ है। आईईए ने रिपोर्ट में दावा किया कि भारत 2024 में स्वच्छ ऊर्जा के लिए विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) से मिलने वाली फंडिंग का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत को करीब 2.4 अरब डॉलर मिले। भारत के बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगातार बढ़ रहा है, जो 2023 में 5 अरब डॉलर पहुंच गया। यह कोविड-19 महामारी से पूर्व के निवेश से लगभग दोगुना है। देश में 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को पाने के लिए व्यापक स्तर पर मांग सृजित करना महत्वपूर्ण है। बेन एंड कंपनी, उद्योग मंडल सीआईआई और रॉकी माउंटेन इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत रणनीतिक क्षेत्रों के चयन, मिश्रण, सार्वजनिक खरीद का लाभ उठाने और निर्यात अवसरों के साथ तालमेल बिठाकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हरित हाइड्रोजन को अपनाने से जुड़े जोखिम से निपटने के लिए कच्चे माल की लागत को कम करने समेत कई उपाय करने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 तक तेल शोधन संयंत्रों से हरित हाइड्रोजन की मांग 20 लाख टन, उर्वरक क्षेत्र से 9 लाख टन और पाइप वाली प्राकृतिक गैस से एक लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यात के मोर्चे पर हरित हाइड्रोजन निर्यात आठ से 11 लाख टन के बीच उत्पन्न हो सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई : धर्मपाल सिंह

कुशीनगर।

*** भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा अनुसूचित समाज में फैलाई गई भ्रांतियां दूर करें कार्यकर्ता**

*** 29 जून को प्रत्येक बूथ पर चलेगा विशेष अभियान**

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को कसया के एक रिसार्ट में अलग-अलग दो बैठकों में सम्मिलित हुए । प्रदेश महामंत्री संगठन अनुसूचित मोर्चा एवं शक्ति केंद्र प्रवासी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई है। प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों के उत्थान,मान और की सम्मान की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है। अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारते हुए वंचित समाज को सशक्त किया है। प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया। जिससे नई पीढ़ी पंच तीर्थों के माध्यम से बाबा साहेब के विचारों से को समझे और उन विचारों से जुडकर संविधान की मजबूती व देश के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे। स्वच्छता कर्मियों के पैर धुलाकर मोदी जी ने विश्व को संदेश दिया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति व प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ है और सम्माननीय है। आज मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना ग़रीब व वंचित वर्ग के आर्थिक व सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित है। जिसका सबसे अधिक लाभ अनुसूचित वर्ग को मिल रहा है। भाजपा सरकार के प्रत्येक निर्णय में संविधान व लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प निहित है।कहा कि कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब को अपमानित करने का कोई मौका नही छोड़ा, दो दो बार उन्हें चुनाव में हराने के लिए अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न भी नही दिया। धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम सभी मोदी सरकार और योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं, ऐतिहासिक निर्णय, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए किए गए कार्य, बाबा साहेब के सम्मान में किए गए कार्यों के साथ घर घर पहुंचकर जनसंवाद करें और उनके बीच में तथ्यों के साथ चर्चा करें कि कैसे कांग्रेस और सपा ने लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किया और बाबा साहेब के दिए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करते हुए अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार किया। शक्ति केंद्र प्रवासी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री संगठन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ÷पोलिटिकल÷ के साथ पुण्य का कार्य भी करते हैं। कहा कि बूथों की मजबूती शक्तिकेन्द्र प्रवासियों की जिम्मेदारी है उन्होंने बूथों पर मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सरकार की सबसे बड़ी योजना है ऐसे में बूथ स्तर पर पात्र आयुष्मान धारकों का कार्ड बनवाने के लिये कैंपो का आयोजन करें। कहा कि 21 जून को योग दिवस मनाना है। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जिले में संगोष्ठी होगी, 25 जून को आपातकाल की संगोष्ठी व प्रदर्शनी लगानी है 29 जून को हर बूथों पर पौधरोपण कार्यक्रम करना है तथा मनकी बात भी उसी दिन सभी बूथों पर सुनना है। उन्होंने कहा आप सभी शक्तिकेन्द्र प्रवासी वरिष्ठ कार्यकर्ता है ऐसे में शक्तिकेन्द्र को पावर सेंटर के रूप में विकसित करें तथा बूथों के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में प्रतिभाग करायें। उन्होंने कहा कि हमे ध्यान देना होगा की प्रत्येक बूथों पर हमारी मजबूत टीम बन सके।कहा कि प्राथमिक सदस्यों, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, सक्रिय सदस्य व अन्य सभी बूथों के कार्यकर्ताओं को मोबलाइज करना है वाइब्रेट करना है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो बूथों पर भी सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक दल है जहां जाति पांति नहीं चलती है। आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेई और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही संविधान के मूल भावना का सम्मान बाबासाहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर के सपनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। दोनों बैठकों की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि पार्टी द्वारा जो भी अभियान दिए जा रहे हैं उसे जनपद कुशीनगर के परिश्रमी कार्यकर्ता निरंतर बेहतर परिणाम दे रहे हैं। संचालन जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी ने किया।

दिनचर्या में शामिल करें योगः रजनी साहू

जौनपुर। मन को शांत, तनाव को दूर करने का आसान तरीका योग है। इसे सभी को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। यह आह्वान नेशनल योग प्रशिक्षक रजनी साहू ने विश्व योग दिवस के पूर्व बेला पर लायंस क्लब जौनपुर रॉयल द्वारा गोसाई रामलीला मैदान उर्दू बाजार में आयोजित योगा वर्कशॉप में किया। साथ ही कहा कि योग शारीरिक व मानसिक दोनों दृष्टिकोण से लाभदायक है। क्लब अध्यक्ष मधुसूदन बैंकर ने कहा कि क्लब ने अपने सदस्यों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से योगा वर्कशॉप का आयोजन किया है। योग को अपनी जीवनशैली का? अहम हिस्सा बनाने से हम अनेक बिमारियों से बच सकते हैं। संस्थापक अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग प्राचीन काल से ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया है। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं को करते हुए इसके महत्व को समझा। अन्त में सभी लोगों ने योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष मधुसूदन बैंकर ने योगाचार्या रजनी साहू को अंगवस्त्रम व गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर एकता गुप्ता, संजीव साहू, अभिताश गुप्ता, विनोद अग्रहरि, आशीष गुप्ता, विष्णु गौड़, जितेंद्र सोनी, बालकृष्ण साहू, अभिषेक जायसवाल आदि उपस्थित रहे। अन्त में क्लब सचिव अजय सोनकर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

छात्र नेता को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी

रुद्रपुर (देवरिया)। पूर्वी तिवारी टोला निवासी एवं छात्र राजनीति से जुड़े सक्रिय युवा नेता मनीष मिश्रा को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। मनीष मिश्रा ने इस संबंध में साइबर क्राइम शाखा को लिखित शिकायत दी है और आरोपी की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनीष मिश्रा को एक अज्ञात फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक भाषा में अपशब्द लिखे गए और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी और अभद्र भाषा के प्रयोग से मनीष मिश्रा एवं उनके परिजन भयभीत हैं। उन्होंने बताया कि वह छात्र हितों के लिए सदैव मुखर रहते हैं और समाज से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं, जिससे असामाजिक तत्व उनकी छवि को धूमिल करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष मिश्रा ने प्रभारी निरीक्षक, साइबर क्राइम देवरिया को दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि एक फेसबुक आईडी से मेरे खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच कर संबंधित आरोपी को चिन्हित करने और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

अवैध मांस विक्रेताओं पर खाद्य विभाग की सख्ती, 8 दुकानों का चालान

देवरिया।

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार मिल रही जनशिकायतों और गंदगी को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 16 मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। यह अभियान 10 जून को भीखमपुर रोड, महुआनी चौराहा और महुआपाटन से शुरू हुआ, जो 16 जून को बरियारपुर, बरहड़ा चौराहा होते हुए 19 जून को रुद्रपुर मोड़, सोनूघाट, शहीद गेट, भटवलिया चौराहा और भटनी तक जारी रहा। निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर खुले में जानवर काटे जाते हुए, अस्वास्थ्यकर तरीके से मांस बेचते हुए और प्रदूषणकारी परिस्थितियों में विक्रय करते हुए पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम और नियमों के उल्लंघन पर कुल 8 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन दुकानों पर न तो नगर पालिका की अनिवार्य एनओसी पाई गई, न ही सफाई व्यवस्था का कोई पालन होता मिला। कई दुकानों पर मांस खुले में प्रदर्शित किया गया था और कचरा खुले में फेंका जा रहा था, जिससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा था, बल्कि आसपास के वातावरण में भी भारी दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बढ़ गया था।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र ने कहा कि ऐसे सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त करें और मांस विक्रय के लिए अस्थायी स्टॉल स्थापित करते समय पर्दा, काला शीशा तथा ढकी हुई टंकियों का उपयोग करें। साथ ही अवशेष व अपशिष्ट पदार्थों को ढंक कर रखना अनिवार्य किया गया है। खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे स्वच्छता मानकों का पालन करने वाले दुकानों से ही सामग्री क्रय करें।

भटनी जंक्शन पर तेज़ी से चल रहा है पुनर्विकास कार्य - रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने निरीक्षण कर दिए निर्देश

भटनी देवरिया।

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी मंडल के भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की समीक्षा दिन बृहस्पतिवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने की। इस अवसर पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे सुश्री सौम्या माथुर और मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव सहित रेलवे मुख्यालय गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 42.62 करोड़ की लागत से हो रहा है कायाकल्प

अध्यक्ष सतीश कुमार ने गोरखपुर-छपरा रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करते हुए देवरिया सदर और भटनी स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायज़ा लिया और संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों को गुणवत्ता और मयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

भटनी स्टेशन पर 42.62 करोड़ की लागत से चल रहे प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। सरकुलेटिंग एरिया का सुधार, सम्पर्क मार्ग और जल निकासी व्यवस्था,यात्रियों के लिए पाथवे निर्माण,आगमन-प्रस्थान भवन का विकास, दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग, नए शौचालयों का निर्माण, प्लेटफार्मों का उच्चीकरण एवं सरफेस सुधार, प्लेटफार्मों पर शेड निर्माण, यात्री प्रतीक्षालय का नवीनीकरण, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल क्लॉक, ऑटो एनाउंसमेंट सिस्टम

अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटरों में सुधार

स्टेशन पर लिफ्ट, फसाड लाइटिंग, साइनेज, लाइटिंग एवं पंखों की आधुनिक व्यवस्था। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने इन सभी प्रगतिशील कार्यों की गति को और तेज़ करने की बात कही तथा सभी कार्यों को शीघ्र और पूर्ण गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

वन स्टॉप सेंटर में किया गया योगाभ्यास

कुशीनगर । जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि दिनांक 21 जून 2025 को विश्व योगा दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दिनांक 20.06.2025 को प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक योग सत्र का आयोजन वन स्टॉप सेन्टर रविन्द्रनगर परिसर में किया गया। जिसमें योगा प्रशिक्षक अभय रंजन मिश्रा एवं श्रीमती रंजना सिंह योगा सहायक द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें प्रसिद्ध कुमार राहुल वरिष्ठ सहायक, अमित राय अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, कुशीनगर, नलिन सिंह, डी0एम0सी0, अभिषेक कुमार सिंह प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर, विनय कुमार शर्मा, संरक्षण अधिकारी, श्रीमती अंजली पाण्डेय विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, श्रीमती रीता यादव सेन्टर मैनेजर वन स्टॉप सेन्टर, इम्तेयाज अली फार्मासिस्ट, श्रीमती प्रीति सिंह, वन्दना कुशवाहा, अनिता देवी, सुनिता पाण्डेय, संगीता मिश्रा, ऋषिराज पाण्डेय, राजू कुमार, आकाश तिवारी, गंगाधर मिश्रा, मुनीष कुमार, मोहन लाल गुप्ता, आदर्श सिंह, ऋषिकेश सिंह, प्रकाश चन्द भारती तथा सेन्टर में मौजुद संवासिनि आदि द्वारा योगाभ्यास किया गया।

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत

कुशीनगर । अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर पर प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र दामोदरदास मोदी का भव्य स्वागत अभिनंदन हुआ। प्रधानमंत्री का कुशीनगर में ट्रांसिट विजिट को लेकर आगमन हुआ था जहां उनका हवाई जहाज उतरा और यहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर से सिवान बिहार में कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम समापन के वापसी के समय भी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं मंत्रियों पदाधिकारी के साथ जिला प्रशासन की तरफ से विदा किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही,जनपद कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा सांसद कुशीनगर विजय दुबे, लोकसभा सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह,भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक सहजानंद राय, जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, विधायक पीएन पाठक, विवेकानंद पांडे मनीष जायसवाल डॉ असीम राय, सुरेंद्र कुशवाहा, विनय प्रकाश गोंड, मोहन वर्मा , विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह,जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, नगर पालिका कुशीनगर अध्यक्ष किरन जायसवाल नगर पालिका पडरौना अध्यक्ष विनय जायसवाल,एडीजीपी के एस प्रताप कुमार, कमिश्नर गोरखपुर अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, इसी प्रकार प्रधानमंत्री के विदा होते समय पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा जयप्रकाश शाही जगदंबा सिंह अखिलेश मिश्रा ललन मिश्रा पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी पवन केडिया मदन गोविंद राव, दीप लाल भारती आदि लोगों उपस्थित रहे।

डीएम ने पीली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का किया निरीक्षण

जौनपुर।

जिलाधिकारी डा0 दिनेश चंद्र ने पीली नदी के जीर्णोद्धार कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति के संबंध में जानकारी लिया। इस दौरान अपेक्षा के अनुरूप कार्य तीव्र गति से होते हुये पाया गया जिस पर उन्होंने कार्य में लगीं उपजिलाधिकारी बदलापुर योगिता सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग, खंड विकास अधिकारी बदलापुर, ग्राम प्रधान, श्रमिक सहित अन्य की प्रशंसा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में पर्यावरण और जल संवर्धन के कार्य किये जायं जिसके क्रम में पीली नदी को चिन्हित करते हुए जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही नदी के किनारे लगभग 1000 पौधे रोपित करने की भी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा, मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विधायक बदलापुर सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण के निर्देशन में ग्राम प्रधानगण, सिंचाई विभाग के अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के समन्वय से पीली नदी के जीर्णोद्धार के समस्त कार्य को श्रम के आधार पर तेजी से किया जा रहा है। नदी का स्वरूप जहां पर खत्म हो गया था, उस पॉइंट को चिन्हित करते हुए ठीक करने का कार्य किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक जल संचय हो सके। इस कार्य में 8 पोकलेन मशीन लगातार कार्य कर रही है और अधिक संसाधन बढ़ाने के भी प्रयास किया जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

इस दौरान उन्होंने ग्राम देवरिया, नुरूद्दीनपुर में स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए शासन के विभिन्न योजनाओं के सन्दर्भ में जानकारी देते हुए इच्छुक लोगों को बकरी पालन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बदलापुर योगिता सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई, ग्राम प्रधानगण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मस्जिद के बाहर से दिनदहाड़े बाइक चोरी

तमकुही राज कुशीनगर । पटहेरवा थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत पगरा पड़री में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब बसंतपुर टोला स्थित मस्जिद के बाहर से दिनदहाड़े एक युवक की बाइक चोरी हो गई। जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद आए गांव के धनटोली निवासी शमशाद अंसारी ने अपनी बाइक यूपी 57 एयू 2566 मस्जिद के बाहर खड़ी की थी। नमाज समाप्त कर जब वह बाहर निकले तो बाइक गायब थी। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से हैरान रह गए। तुरंत ही पीड़ित ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। मस्जिद के आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। शमशाद अंसारी ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि यदि किसी को उनकी बाइक के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दें या नजदीकी पुलिस को अवगत कराएं। दिनदहाड़े मस्जिद जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान से बाइक चोरी की घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खैरटिया पुल चौराहे पर लगातार हो रहे हादसेः स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खैरटिया पुल चौराहे पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से हादसों का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य पश्चिमी गंडक नहर का मार्ग खैरटिया पुल चौराहे से होकर कप्तानगंज-नौरंगिया तक जाता है। चार साल पहले मुख्य नहर मार्ग के टू लेन होने से वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। नहर मार्ग से आने वाले राहगीर स्टेट मार्ग को पार करते समय हादसों का शिकार हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल चंद्रिका, नाथू और महंथ समेत अन्य ग्रामीणों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर बन जाने से हादसों में कमी आएगी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिए कोई कदम न उठाए जाने से ग्रामीण नाराज हैं।

बंटवारे के विवाद में पिता-पुत्री पर हमलाः बेटे, बहू और पड़ोसी ने की मारपीट; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर । नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में पारिवारिक बंटवारे को लेकर हिंसा का मामला सामने आया है। पीड़ित हफिजुल्लाह और उनकी 21 वर्षीय बेटी रोबिना खातून के साथ मारपीट की गई। हफिजुल्लाह ने अपने बड़े बेटे महमूद अंसारी, बहू अमीन्ना नेशा और पड़ोसी सलामुद्दीन पर हमले का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार, 15 जून की सुबह लगभग 6 बजे बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हुआ। बड़े बेटे ने गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपियों ने मिलकर पिता-पुत्री को लात-घूंसों और डंडों से पीटा। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी।घटना के बाद पीड़ितों ने मेडिकल जांच कराई। इलाज के बाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार शाम 7:45मिनट को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

भटनी नगर में नवागत एसडीओ चंद्रभूषण ने संभाला कार्यभार

भटनी देवरिया।

पहले ही दिन चलाया बकाया व मीटर जांच अभियान

उपभोक्ताओं को दी चेतावनी - जल्द जमा करें बकाया बिल, नहीं तो होगी कार्रवाई

भटनी नगर में विद्युत आपूर्ति को सुचारु बनाने और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से दिन शुक्रवार को एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। नवागत एसडीओ चंद्रभूषण ने पदभार संभालते ही सक्रियता दिखाते हुए नगर के विकास रोड समेत कई मोहल्लों में जेई अमन कुमार और विभागीय टीम के साथ दुकान-दुकान व घर-घर जाकर बिजली मीटर और बकाया बिल की गहन जांच की। जांच के दौरान जिन उपभोक्ताओं पर बिल बकाया पाया गया, उन्हें तत्काल भुगतान करने की सख्त चेतावनी दी गई। एसडीओ चंद्रभूषण ने स्पष्ट किया कि, ÷अब विद्युत विभाग किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई तय है।÷ इस दौरान जेई अमन कुमार ने भी कहा कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार चेतावनी के बावजूद बकाया नहीं जमा किया जाएगा, उनकी बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान कई घरों में लोड की अनियमितता भी पाई गई। कई उपभोक्ता का मीटर 2 किलोवाट के लोड पर दर्ज था, जबकि खपत 4 किलोवाट से अधिक हो रही थी। ऐसे उपभोक्ताओं को लोड बढ़वाने का निर्देश दिया गया। इस विशेष अभियान में संविदा लाइनमैन मंटू विश्वकर्मा, ढेला, उदयभान कुशवाहा सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी भी मौजूद रहे।

प्रधान ने लगाया दबंगों पर रास्ता बंद करने का आरोप , आवागमन बाधित

तमकुही राज कुशीनगर । तमकुही विकास खंड के ग्राम पंचायत जोगिया सुमाली पट्टी के प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है जिससे आवागनम पूरी तरह बाधित हैं जिससे गांव में काफी आक्रोश व्याप्त हैं। प्रधान रमेश प्रसाद ने जिलाधिकारी को दिए शिकायत पत्र में लिखा हैं कि ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग को कुछ लोगों द्वारा पक्का निर्माण करके तथा कुछ भाग पर अतिक्रमण करके पूरी तरह बंद कर दिया गया है जिससे गांव में स्थित परिषदीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं।आधे गांव का संपर्क आधे गांव से कट गया हैं ।लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए खेत के पगडंडी का सहारा लेना पड़ रहा हैं।इस संबंध में इससे पूर्व में भी पीड़ित ग्रामीणों द्वारा रास्ता बंद की शिकायत की जा चुकी हैं ।फिर भी अभी तक बंद रास्ता खुलवाया नहीं गया हैं। ग्रामीण रिंटू राय, कौशल किशोर सिंह,अभय राय, अजीत राय आदि ने मांग की है कि सड़क से तत्काल अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाया जाए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके।

टहलने के दौरान कहासुनी में युवक को चाकू मारा, जिला अस्पताल रेफर

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर । नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के गड़हिया बसंतपुर गांव में की शाम एक गंभीर घटना सामने आई। दो नाबालिग गांव के बाहर पानी टंकी की तरफ टहल रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक नाबालिग ने धारदार हथियार से दूसरे नाबालिग पर हमला कर दिया। एक युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घायल युवक को पहले कोटवा सीएचसी ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना दो संप्रदाय के बीच होने के कारण गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और हमलावर की तलाश शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार यह घटना दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है।एसएचओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई है। पुलिस कैंप कर रही है और हमलावर की तलाश जारी है। घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।